TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-03-06 | Page- 1
ehitavada.com

TFRI's project report gets Union Ministry's green signal

■ Staff Reporter

THE Tropical Forest Research Institute (TFRI) Jabalpur's Detailed Project Report for rejuvenation of river Narmada through forestry intervention has been given green signal by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC). The suggested interventions focus to address three major issues related to river i.e., land degradation in catchment areas, sediment run-off and decreased e-flow.

File Photo

Dr G Rajeshwar Rao, Director TFRI, informed that a mammoth task of preparing DPR of 13 rivers was taken up by various institutes under Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun. Out of 13 DPRs, nine have been submitted to and approved by the ministry. TFRI meticulously proposed a total of 51 site-specific

(Contd on page 2)

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-03-06 | Page- 2
ehitavada.com

TFRI's project report gets Union...

models for agricultural, natural and urban landscapes after conducting 16 consultative meeting in the four states with State Forest dSepartments, academicians, scientists, researchers, bureaucrats and various other stakeholders. The scheme will rejuvenate 83,962.39 hectare of Narmada river basin of Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh and Gujrat states through which the river flows. An amount of Rs. 2127.28 crores were proposed for five years, of which an amount of Rs.1482.40 crores will be for Madhya Pradesh to carry out conservation and forestry interventions in the river scape. The implementation of DPR will be carried out by the respective State Forest Departments and other government agencies.

नर्मदा बेसिन के कायाकल्प पर 2127 करोड़ होंगे खर्च

कायाकल्प ● मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में 84 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का होगा सुधार, केंद्र ने दी स्वीकृति

जबलपुर (नप्र)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआइ) द्वारा तैयार की गई वानिकी के माध्यम से नर्मदा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार नर्मदा बेसिन के कायाकल्प पर 2127 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

इस बारे में डॉ.जी राजेश्वर राव निदेशक टीएफआरआइ ने बताया कि केंद्र से नर्मदा नदी के कायाकल्प की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है। नर्मदा नदी को पुनर्जीवन देने के लिए सुझाए गए हस्तक्षेप मुख्यतः तीन हैं। इनमें पहला जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि क्षरण दूसरा तलछट का कटाव और तीसरा नदी के घटते हुए प्रवाह को संबोधित करने पर केंद्रित होंगे।

13 भेजे, 9 अनुमोदित: डॉ. राजेश्वर राव ने बताया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) देहरादून के संबद्ध संस्थानों ने देश की 13 नदियों की डीपीआर तैयार की। यह सभी डीपीआर भेजने के बाद सिर्फ नौ को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया है।

नर्मदा नदी के पुनर्जीवन के लिए 2187 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कालपी मंडला में नर्मदा के बरगी बांध के जलभराव क्षेत्र का मनोरम दृश्य। ● सौजन्य

मध्य प्रदेश में 1482 करोड़ का उपयोग

पीआरओ निधि मेहता ने बताया कि यह योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के नर्मदा नदी बेसिन के 83,962.39 हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प करेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पांच वर्षों के लिए 2127.28 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई थी। इसमें से 1,482.40 करोड़ मध्य प्रदेश में संरक्षण और वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जाएगा।

16 बैठक, 51 मॉडल

टीएफआरआइ ने चार राज्यों के वन विभाग, शिक्षाविदों, विज्ञानियों, शोधकर्ताओं व अन्य हितधारकों के साथ 16 परामर्शी बैठकें आयोजित की। बैठकों में नर्मदा डीपीआर में कुल 51 साइट-विशिष्ट मॉडल प्रस्तावित किए। डीपीआर का कार्यान्वयन संबंधित राज्य वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

नर्मदा के कायाकल्प को केंद्र से मिली हरी झण्डी

जबलपुर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा तैयार की गई वानिकी के माध्यम से नर्मदा नदी के पुनर्जीवन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। डॉ. जी.राजेश्वर राव, एआरएस, निदेशक, टीएफआरआई ने बताया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के सम्बद्ध संस्थानों द्वारा 13 नदियों की डीपीआर तैयार की गई। इनमें से नौ को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। पाँच वर्षों के लिए 2127.28 करोड़ की राशि प्रस्तावित थी।

दैनिक भास्कर Sat, 06 March 2021 https://epaper.bhas

नर्मदा नदी कायाकल्प के लिए डीपीआर को केन्द्र से मिली स्वीकृति

जबलपुर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई) द्वारा तैयार की गई, वानिकी के माध्यम से नर्मदा नदी के पुनर्जी वन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। सुझाए गए हस्तक्षेप, नदी से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि क्षरण, तलछट का कटाव और नदी के घटते हुए प्रवाह को संबोधित करने पर केंद्रित होंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए टीएफआरआई निदेशक डॉ. जी. राजेश्वर राव ने बताया कि भारत वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के संबद्ध संस्थानों द्वारा 13 नदियों की डीपीआर तैयार की है। 13 नदियों में से 9 को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया है। टीएफआरआई ने 4 राजयों के वन विभागों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विभिन्न अन्य हितधारकों के साथ 16 परामर्शी बैठक आयोजित कर नर्मदा डीपीआर में कुल 51 साइट- विशिष्ट मॉडल प्रस्तावित किए हैं। यह योजना मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के नर्मदा नदी बेसिन के 83,962.39 हेक्टेयर क्षेत्र का काया कल्प करेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पांच वर्षों के लिए रू. 2,127.28 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से रू. 1,482.40 करोड़ मध्यप्रदेश में संरक्षण और वानिकी हस्तक्षेप हेतु उपयोग किया जाएगा। डीपीआर का कार्यान्वयन संबंधित राज्य वन विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।